प्रेरणा और अधिक स्मार्ट: उत्तर प्रदेश में आधार प्रमाणीकरण संपत्ति पंजीकरण को बदल रहा है

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एनआईसी), लखनऊ,**उत्तर प्रदेश** ने संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया में आधार-आधारित प्रमाणीकरण लागू करके इसे और मजबूत बनाया है। यह महत्वपूर्ण सुधार सुरक्षित, नागरिक-हितैषी पहचान सत्यापन प्रदान करता है, जिससे पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता में परिवर्तनकारी लाभ मिल रहे हैं। नागरिक सेवाओं में एक परिवर्तनकारी कदम में, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने उत्तर प्रदेश सरकार के **स्टाम्प और पंजीकरण विभाग** के तहत अपने प्रमुख प्लेटफॉर्म **प्रेरणा (PRERNA - PRoperty Evaluation & RegistratioN Application)** में आधार-आधारित प्रमाणीकरण को सहजता से एकीकृत किया है। **1 फरवरी, 2026** से प्रभावी, यह ऐतिहासिक पहल पूरे राज्य में संपत्ति पंजीकरण की सुरक्षा और सरलता को पुनः परिभाषित करती है।

महत्वपूर्ण क्षेत्र में विश्वास का पुनर्निर्माण

प्रेरणा को पारंपरिक जटिल प्रणालियों से दूर हटकर संपत्ति पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए तैयार किया गया था। आधार प्रमाणीकरण का एकीकरण इसका अब तक का सबसे महत्वपूर्ण उन्नयन है, जो किसी भी संपत्ति लेनदेन की आधारशिला - पहचान सत्यापन - को सीधे संबोधित करता है। यह रणनीतिक कदम 'डिजिटल इंडिया' के विजन के साथ शक्तिशाली ढंग से मेल खाता है, जो उत्तर प्रदेश को सुरक्षित, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित डिजिटल शासन में अग्रणी बनाता है।

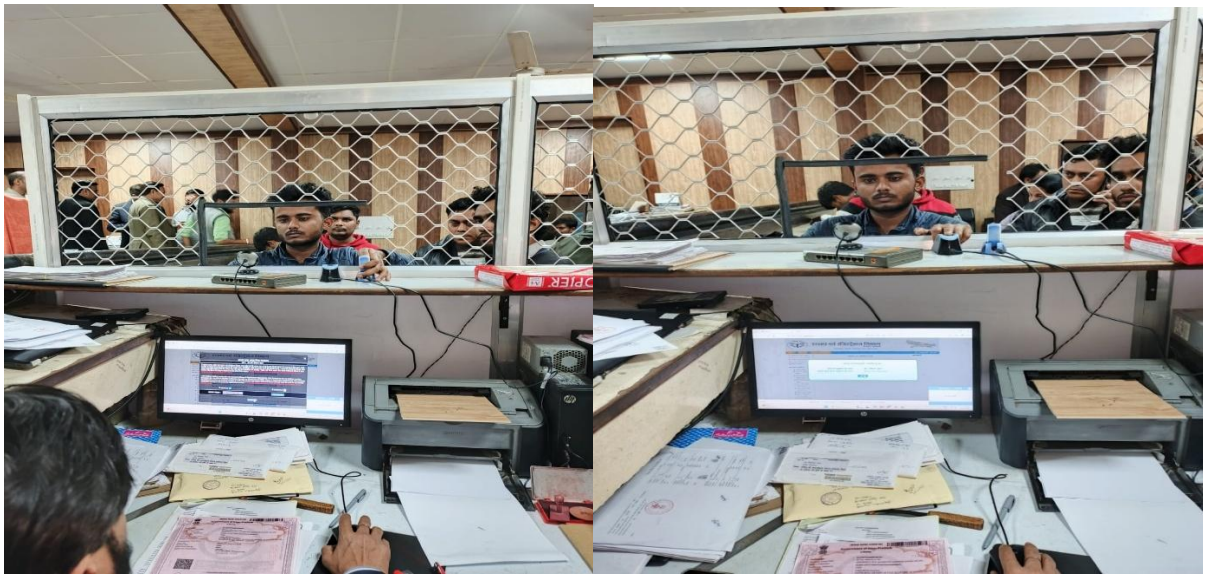

उप-पंजीयक कार्यालय, लखनऊ में आधार आधारित प्रामाणिकरण

राज्यव्यापी कार्यान्वयन: प्रौद्योगिकी और सुगम्यता का संगम

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के साथ घनिष्ठ सहयोग में सूक्ष्म योजना के बाद, एनआईसी उत्तर प्रदेश ने **उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सभी 383 उप-रजिस्ट्रार कार्यालयों** में इस मॉड्यूल को सफलतापूर्वक तैनात और लागू किया है। यह प्रणाली विविध नागरिक आवश्यकताओं के अनुरूप लचीली, सहमति-आधारित प्रमाणीकरण प्रदान करती है:

1. **आवेदक स्तर पर आधार प्रमाणीकरण:** संपत्ति पंजीकरण में शामिल सभी पक्ष, जिनमें गवाह शामिल हैं, अपनी आधार-लिंक्ड मोबाइल संख्या पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से, अपनी सहमति से, अपने आधार नंबर का उपयोग करके आधार प्रमाणीकरण कर सकते हैं।
2. **अधिकारी के समक्ष उप-रजिस्ट्रार कार्यालय स्तर पर आधार प्रमाणीकरण:** संपत्ति पंजीकरण में शामिल सभी पक्ष, जिनमें उप-रजिस्ट्रार कार्यालय में अधिकारी के समक्ष उपस्थित गवाह शामिल हैं, बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पद्धति का उपयोग करके, अपनी सहमति से आधार प्रमाणीकरण कर सकते हैं।

स्वीकृति एवं टीम प्रयास

इस सफल कार्यान्वयन को **श्री आशेष कुमार अग्रवाल, डीडीजी और एसआईओ, एनआईसी उत्तर प्रदेश** के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में संभव बनाया गया। इस महत्वपूर्ण मॉड्यूल के निर्दोष एकीकरण एवं परिनियोजन में उनकी रणनीतिक देखरेख एवं दृढ़ समर्थन निर्णायक सिद्ध हुआ। प्रमाणीकरण मॉड्यूल के समर्पित विकास एवं निर्बाध परिनियोजन का कार्य निम्न अधिकारियो द्वारा किया गया|

श्री राजेश कुमार त्रिपाठी, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (विभागाध्यक्ष)

श्री जगदीश पांडेय, संयुक्त निदेशक

श्री घनश्याम वर्मा, वैज्ञानिक अधिकारी

ठोस परिणाम: प्रौद्योगिकी से परे

कार्यान्वयन तत्काल और दूरगामी लाभ प्रदान करता है:

- **मजबूत पारदर्शिता और सुरक्षा:** जमीन और संपत्ति लेनदेन लंबे समय से प्रतिरूपण, नकली पहचान और बहु-पंजीकरण के माध्यम से धोखाधड़ी के प्रति संवेदनशील रहे हैं। आधार सत्यापन वास्तविक पक्षों की भौतिक उपस्थिति को अनिवार्य करता है, जिससे पहचान के दुरुपयोग और धोखाधड़ी वाले हस्तांतरण को काफी कम किया जा सकता है।
- **उन्नत नागरिक अनुभव:** मैन्युअल कागजी कार्रवाई और व्यक्तिगत सत्यापन में महत्वपूर्ण कमी, जिसके परिणामस्वरूप तेज और अधिक कुशल सेवा वितरण होता है।
- **परिचालन दक्षता:** स्वचालन से विभागीय संसाधन मुक्त होते हैं, जिससे अधिकारी मुख्य नियामक और सेवा-उन्मुख कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
- **अटल ऑडिट ट्रेल:** प्रत्येक प्रमाणीकरण एक सुरक्षित रिकॉर्ड उत्पन्न करता है, जो जवाबदेही को मजबूत करता है और संपत्ति पंजीकरण से संबंधित भविष्य की जांचों में सहायता करता है।

PRERNA Gets Smarter: Aadhaar Authentication Transforms Property Registration in Uttar Pradesh

National Informatics Centre (NIC), Uttar Pradesh, Lucknow has fortified the property registration process by implementing the Aadhaar-based Authentication in Property Registration. This critical enhancement delivers secure, citizen-friendly identity verification, driving transformative gains in transparency and administrative efficiency.

In a transformative move for citizen services, the National Informatics Centre has seamlessly integrated Aadhaar-based Authentication into its flagship **PRERNA (PRoperty Evaluation & RegistratioN Application) platform** under the **Stamp and Registration Department, Government of Uttar Pradesh**. Effective from **February 1st, 2026**, this landmark initiative redefines the security and simplicity of property registration across the state.

Re-engineering Trust in Critical Sector

PRERNA was conceived to automate the entire property registration process, moving away from cumbersome conventional systems. The integration of Aadhaar authentication marks its most significant upgrade yet, directly addressing identity verification—the cornerstone of any property transaction. This strategic step powerfully aligns with the 'Digital India' vision, placing Uttar Pradesh at the forefront of secure, transparent, and citizen-centric digital governance.

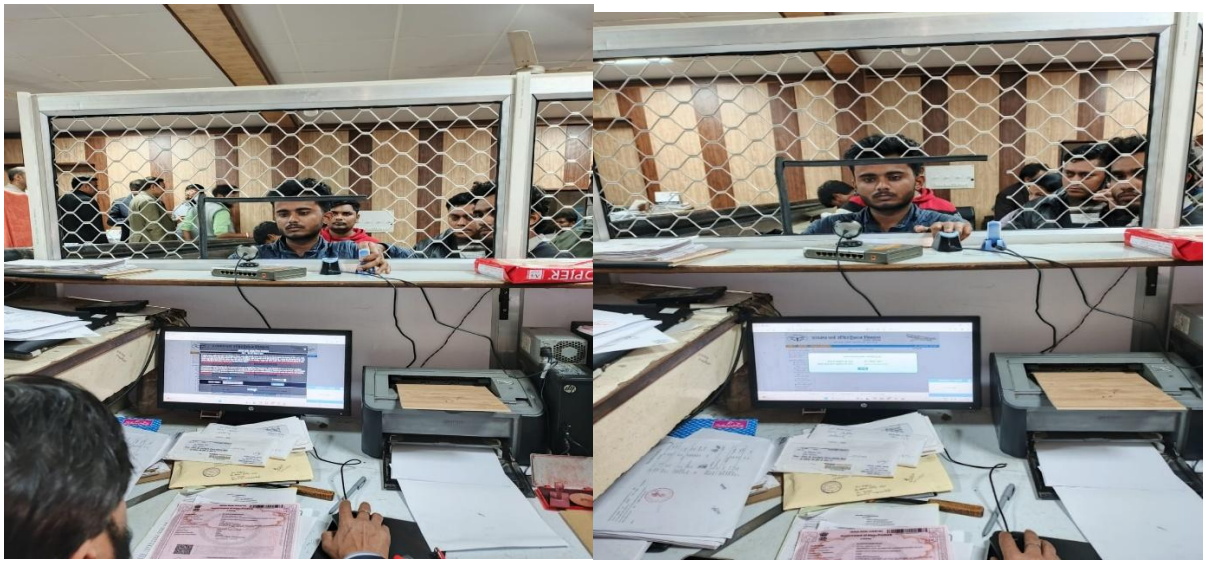

Aadhaar-based Authentication at Sub-Registrar Office, Lucknow

A Statewide Rollout: Technology Meets Accessibility

Following meticulous planning in close collaboration with the Unique Identification Authority of India (UIDAI), NIC Uttar Pradesh has successfully deployed the module and implemented across all **383 Sub-Registrar Offices in 75 districts of Uttar Pradesh**. The system offers flexible, consent-based authentication to suit diverse citizen needs:

1. **Aadhaar authentication at Applicant level:** All parties involved in property registration, including witnesses, can perform Aadhaar authentication using their Aadhaar number, with their own consent, through an OTP received on their Aadhaar-linked mobile number.
2. **Aadhaar authentication at Sub-Registrar Office level before officer:** All parties involved in property registration, including witnesses present at the SR office before the officer, can perform Aadhaar authentication using the Biometric Aadhaar Authentication method, with their own consent.

Acknowledgment & Team Effort

This successful implementation was made possible under the guidance and leadership of **Shri Ashesh Kumar Agarwal, DDG & SIO, NIC Uttar Pradesh**. Their strategic oversight and steadfast support were instrumental in the flawless integration and deployment of this pivotal module.

The dedicated development and seamless deployment of the authentication module were performed by

Shri Rajesh Kumar Tripathi, Sr. Technical Director (HOD)

Shri Jagdish Pandey, Joint Director

Shri Ghanshyam Verma, Scientific Officer

Tangible Outcomes: Beyond Technology

The implementation delivers immediate and far-reaching benefits:

- **Fortified Transparency & Security**: Land and property transactions have long been vulnerable to fraud through impersonation, forged identities, and multiple registrations. Aadhaar verification mandates the physical presence of genuine parties, greatly minimizing identity misuse and fraudulent transfers.
- **Enhanced Citizen Experience**: Significant reduction in manual paperwork and in-person verification, resulting in faster and more efficient service delivery.
- **Operational Efficiency:** Automation frees up departmental resources, allowing officials to focus on core regulatory and service-oriented tasks.
- **Unshakeable Audit Trail:** Every authentication generates a secure record, strengthening accountability and supporting future queries related to property registration.